SHRI K.G. KENYE (Nagaland): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Corruption in implementation of MUDRA Yojana Scheme

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। युवाओं में व्याप्त बेरोज़गारी की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक 'मुद्रा ऋण योजना' की घोषणा की थी और उसको बहुत hype दिया गया था। यह भी पता लगा है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोन दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है। 'मुद्रा ऋण योजना' सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसमें दलालों का और बैंक मैनेजर्स का nexus बन गया है, जिसके कारण बैंकों का जो फाइनेंस है, वह खराब हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: I am not able to understand why Monday has become a special day. People are getting involved into side talk. I request every one of you that if you want to talk, please go out.

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मेरा समय कम हो रहा है।

श्री सभापति: मैं यह आपको नहीं कह रहा हूं। समय की समस्या को मैं समझ लूंगा, आप चिंता मत करिए।

आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग बात कर रहे हैं, वे कृपया बाहर जाकर आपस में बातचीत करके, फिर वापस आ सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले भी मैंने यह कहा था कि यदि किसी को भी मंत्रियों सहित किसी मेम्बर से मिलना है, तो आप वहीं जाकर, उनकी बगल में चुपचाप बैठकर, क्वाइटली बात करिए। खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं है। बार-बार मुझे इन्हीं बातों को कहना पड़े, यह शोभा नहीं देता है। चेयरमैन को बार-बार यह कहना पड़ता है कि सामने से हट जाइए। आप सभी लोग इस बात को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि हम सबके आचरण को पूरे भारत के लोग देख रहे हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मुझे टाइम का प्रोटेक्शन दीजिए।

श्री सभापति: टाइम मैं देख लूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मेरा जो जनपद है, वहां लखीमपुर खीरी में बहुत बड़े पैमाने पर बैंक मैनेजर्स और दलालों के नेक्सस का प्रकरण सामने आया है, जिसमें बहुत सारे लोग ठगे गए हैं। उसमें FIRs भी दर्ज कराये गये हैं। आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि वह "मुद्रा ऋण योजना" की effective monitoring के लिए कोई special committee बना कर जांच कराने का काम करे, जिससे युवाओं को ठगे जाने से बचाया जा सके एवं बैंकों का NPA बढ़ने से रोका जा सके। सर, बैंकों के जो कर्मचारी कमीशनखोरी करके लोगों को लोन दे रहे हैं, NPA बढ़ा रहे हैं, उनको दंडित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं यह बात आपके माध्यम से सबके सामने लाना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गऐ विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गऐ विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री प्रशांत नंदा (ओडिशा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गऐ विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Natural calamities caused by incessant rains in Uttarakhand

श्री अनिल बलूनी (उत्तराखंड): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे राज्य उत्तराखंड में अतिवृष्टि एवं बादल फटने की घटनाओं से उत्पन्न परिस्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, विगत कुछ वर्षों से उत्तराखंड में अत्यधिक वर्षा एवं बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। शायद जलवायु परिवतन का दुष्प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। नदी-नाले उफान पर हैं, landslide के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग जगह-जगह बाधित हो रहे हैं। पेयजल आपूर्ति पर एवं विद्युत आपूर्ति पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं, लोगों के घर landslide में बह गये हैं।

सभापति जी, इस विकट समय में राज्य सरकार पूरे मनोयोग के साथ राहत कार्यों में लगी हुई है। कई स्थानों पर राहत कैम्प भी लगाये गए हैं, किन्तु आप जानत हैं कि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं। सभापति जी, मेरा आग्रह कि इस आपदा की घड़ी में राज्य सरकार को सहयोग किया जाना चाहिए।

उत्तराखंड आपदाओं के प्रतिं सवेदनशील राज्य है। ऐसे मे कभी भी कोई बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। अतः मेरा निवेदन है कि NDRF की एक इकाई स्थायी रूप से उत्तराखंड में स्थापित होनी चाहिए, धन्यवाद।

Need to make local language mandatory for all recruitments by I.B.P.S

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, the centralised recruitment system in the banking industry is a blatant violation of the federal structure of our country. The regional recruitments are completely ignored by allowing people from other States and far away States which has created unrest among the local-language speaking people.

Sir, in Karnataka alone, out of 18,000 recruitments, only 1,060 have been selected in the local language category. In earlier recruitments, there was a clause saying, 'The knowledge of local language is compulsory.' Now, it is changed to, 'The knowledge of local language is desirable.' Sir, this has created problems. Among the people working in rural areas or in semi-urban areas who don't know the local language and the local people,